

## मडि-डे मील कार्यक्रम की चुनौतियाँ

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में मडि-डे मील कार्यक्रम और उसकी चुनौतियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

### संदर्भ

देश भर के सरकारी स्कूलों में मडि-डे मील को दैनिकीय का हिस्सा बनाए हुए लगभग 2 दशक बीत चुके हैं। देशव्यापी स्तर पर दो दशकीय इस लंबी यात्रा ने मडि-डे मील कार्यक्रम की सुधार प्रक्रिया को काफी धीमा बना दिया है, परंतु इससे जुड़ी घटनाएँ अनवरत सामने आती रही हैं। हाल में मडि-डे मील से जुड़ी एक ऐसी ही घटना देखी गई जिसमें पानी से भरी एक बाल्टी में एक लीटर दूध मिला दिया गया ताकि उसे स्कूल में मौजूद 80 बच्चों के बीच बाँटा जा सके। इस प्रकार की घटनाएँ ज़ाहिर तौर पर शर्मनाक हैं और यह स्पष्ट करती हैं कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर जल्द-से-जल्द गंभीरता से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

### मडि-डे मील कार्यक्रम

- मडि-डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था।
- इसके पश्चात् सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेनू आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई।
- इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु नमिन प्राथमिक स्तर के लिये प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8-12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिये न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है।
- मडि-डे मील कार्यक्रम एक बहुदेशीय कार्यक्रम है तथा यह राष्ट्र की भावी पीढ़ी के पोषण एवं विकास से जुड़ा हुआ है। इसके प्रमुख उद्देश्य नमिनलिखित हैं-
  - प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को बढ़ावा देना।
  - विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि तथा छात्रों को स्कूल में आने के लिये प्रोत्साहित करना।
  - स्कूल ड्राप-आउट को रोकना।
  - बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में वृद्धि तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा देना।

### कार्यक्रम की आवश्यकता

- हाल ही में 'काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट' नामक एक NGO द्वारा किये गए अध्ययन में सामने आया था कि वर्तमान में 6-18 वर्ष आयु वर्ग के 4.5 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आयु वर्ग के कुल बच्चों का लगभग 16.1 प्रतिशत है। वदिति हो कि इनमें से अधिकांश को मुफ्त और अनविर्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।
  - आँकड़ों की मानें तो ओडिशा (20.6 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (21.4 प्रतिशत) और गुजरात (19.1 प्रतिशत) जैसे बड़े राज्यों में प्रत्येक पाँचवाँ बच्चा स्कूली शिक्षा से वंचित है।
  - अध्ययन में यह भी सामने आया था कि स्कूली शिक्षा प्राप्त न कर पाने वाले कुल बच्चों में से तकरीबन 99.34 प्रतिशत बच्चे आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग से थे। अध्ययन में पाया गया कि लगभग 58.19 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनके पति की सालाना आमदनी 50000 से भी कम है।
  - साथ ही स्कूल न जाने वाले कुल बच्चों में से लगभग 51.18 प्रतिशत के पति और 88.45 प्रतिशत की माताएँ अशिक्षित हैं।
- इसके अलावा भारत में बच्चों से जुड़ी एक अन्य समस्या अल्पपोषण की है। हाल ही में जारी 'द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन- 2019' के अनुसार, विश्व में 5 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक 3 बच्चों में से एक बच्चा कुपोषण अथवा अल्पवजन की समस्या से ग्रस्त है।
- उपरोक्त आँकड़ों से भारतीय बच्चों के बुनियादी मानवाधिकारों जैसे- भोजन और शिक्षा तक पहुँच आदि की स्थिति का स्पष्ट तौर पर पता चलता है। साथ ही ये आँकड़े स्कूली बच्चों की शैक्षिक और पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये एक नीतितंत्र चुनौती भी प्रस्तुत करते हैं।

### मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का है लंबा इतिहास

- वदिति हो कऱ भारतीय वदियालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का एक लंबा इतऱिास रहा है । भारत में छात्रों को भोजन प्रदान करने की अवधारणा पहली बार वर्ष 1925 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा तमलिनाडु के प्राथमकि स्कूलों में शुरु की गई थी ।
- बाद में फ्रांसीसी प्रशासन ने भी 1930 के दशक के आरंभ में केंद्रशासति प्रदेश पुदुचेरी में इसकी शुरुआत की ।
- आज़ादी के बाद वर्ष 1962-63 के दौरान वदियालयों में और अधकि बच्चों को आकर्षति करने के उद्देश्य से तमलिनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में एक बार फरि से इस तरह की योजना शुरु की गई ।
- योजना के व्यापक प्रसार के कारण वर्ष 1985 में गुजरात और केरल की सरकारों ने भी इसे लागू करने का नरिणय लयिा । हालाँकि कुछ कारणों से जल्द ही गुजरात में इस योजना को बंद कर दयिा गया, परंतु केरल में यह चालू रही और आवश्यकतानुसार इसमें सुधार भी कयिा गया ।
- 1990-91 में बारह अन्य राज्य सरकारों ने इस योजना को अपने-अपने राज्य में लागू करने का नरिणय लयिा, जसिके बाद अगस्त 1995 में स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लयिा मडि-डे मील कार्यक्रम की शुरुआत की गई ।

## कार्यक्रम का महत्त्व

- यह योजना एक साथ खाने की आदत को बढ़ावा देकर स्कूली बच्चों के बीच समाजीकरण को बढ़ाने में मदद करती है । एक साथ दोपहर का भोजन करने से वभिनिन धार्मकि समूहों के बीच एकता और समरसता में बढ़ोतरी होती है ।
  - वभिनिन जाति, धर्मों और मज़हबों के बीच भेदभाव को कम कर यह वदियारथियों को एक अच्छा नागरकि बनाने के लयिा प्रेरति करती है ।
- यह योजना गरीब बच्चों के माता-पतिा के लयिा बच्चों को स्कूल भेजने हेतु एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है । साथ ही देश की साक्षरता दर को बढ़ाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमकिा नभिाती है ।
- यह योजना देश में गरीबी कम करने में भी महत्त्वपूर्ण साबति हो सकती है, क्योंकि इससे जतिने ज़्यादा लोग शक्ति और स्वस्थ होंगे वे अर्थव्यवस्था के वकिास में उतना ही अधकि योगदान देंगे ।
- उल्लेखनीय है कि मडि-डे मील कार्यक्रम 10 मलियिन से अधकि स्कूलों में 120 मलियिन से अधकि बच्चों को भोजन प्रदान कर यह अपनी तरह का दुनयिा का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया है, जसिके कारण इसके सफल कार्यान्वयन के लयिा एक वशाल कार्यबल की आवश्यकता पड़ती है ।
  - सरकार द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, इस कार्यक्रम से पूरे देश में तकरीबन 26 लाख लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है ।
- मडि-डे मील कार्यक्रम के नरिधारति दशिा-नरिदेशों के तहत जहाँ तक संभव हो, सरकार को इस कार्यक्रम के संचालन के लयिा सामुदायकि सहायता और सार्वजनकि-नजिा भागीदारी को प्रोत्साहति करना चाहयिा ।

## चुनौतयिाँ

- **भोजन की गुणवत्ता:** भोजन की गुणवत्ता के संदर्भ में CAG की एक रिपोर्ट के मुताबकि, अध्ययन के दौरान लयिा गए खाद्यान्न के कुल 2,012 नमूनों में से 1,876 पोषण मानकों को पूरा करने में वफिल रहे थे, जसिका अर्थ है कि मडि-डे मील कार्यक्रम के तहत बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन का 80 प्रतिशत गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता है । वशिषज्जों का मानना है कि इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि इस योजना के तहत भोजन की गुणवत्ता से ज़्यादा भोजन की मात्रा पर ध्यान दयिा जाता है । हाल ही में मानव संसाधन वकिास मंत्रालय ने आँकड़ा जारी कयिा था, उन्हें गत 3 वर्षों में घटयिा खाद्य गुणवत्ता को लेकर 15 राज्य और केंद्रशासति प्रदेशों से कुल 35 शकियतें प्राप्त हुई थी । जानकारों का मानना है कि सरकार का ध्यान केवल उन आँकड़ों पर केंद्रति है कि वह कतिने स्कूलों को कवर करने और भोजन पहुँचाने में सक्षम है, कोई भी भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देना चाहता ।
- **जाति और धर्म:** मडि-डे मील कार्यक्रम के संबंध में आने वाली शकियतों में एक बड़ी संख्या जातगित आधार पर होने वाले भेदभाव की भी है । जातगित भेदभाव आधारति अधकिांश घटनाओं में यह देखने को मलतिा है कि यिा तो उच्च जाति के बच्चे SC/ST महिलाओं द्वारा पकाया गया भोजन खाने से मना कर देते हैं या दलति और पछिड़े वर्ग के छात्रों को दूसरों से अलग बैठने के लयिा वविश कयिा जाता है । वदिति हो कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य वभिनिन पृष्ठभूमयिाँ से आए वदियारथियों के मध्य साझेपन की भावना का वकिास करना है, परंतु घटनाएँ बताती हैं कि यह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में वफिल रही है ।
- **नरिीक्षण की व्यवस्था का अभाव:** गाँव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधकिांश बच्चे बहुत गरीब होते हैं और मडि-डे मील कार्यक्रम के तहत मलिने वाला भोजन ही उनके लयिा अंतमि वकिल्प होता है । ऐसे में यह भोजन उनके लयिा खतरनाक भी साबति हो सकता है, क्योंकि भोजन का नरिीक्षण करने के लयिा कोई भी व्यवस्था नहीं होती । वर्ष 2013 की बहिर की घटना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ स्कूल में दोपहर का भोजन खाकर 23 बच्चों की मृत्यु हो गई थी ।
- **भ्रष्टाचार:** वर्ष 2015 में CAG द्वारा कयिा गए एक ऑडिट रिपोर्ट में मडि-डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत वत्तितीय कुप्रबंधन की बात की गई थी । रिपोर्ट में सामने आया था कि कसि प्रकार कर्नाटक में भोजन सप्लाई करने वाली कंपनी ने एक साल के अंदर आवश्यक मापदंडों की तुलना में काफी कम अनाज का प्रयोग कयिा, जो कि स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है ।

## आगे की राह

- लागू होने की तथिाँ से अब तक मडि-डे मील कार्यक्रम को काफी सराहना मलिा है, क्योंकि यह दुनयिा की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है ।
- कई वशिषज्जों का मानना है कि योजना को सफल बनाने के लयिा आवश्यक है कि इसे पाठ्यक्रम का एक पहलू बनाने का प्रयास कयिा जाए । दरअसल इस योजना के पूरणतः सफल न हो पाने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि परिवरितनकारी क्षमता होने के बावजूद भी इस योजना को दान के रूप देखा जाता है ।
  - जबकि इसे सफल बनाने के लयिा यह आवश्यक है कि सरकार इसे बच्चों के प्रति अपने दायतिव के रूप में देखे ।
- योजना के कार्यान्वयन में कार्यबल की कमी एक बड़ी समस्या है जसि पर अतशीघ्र ध्यान दयिा जाना आवश्यक है ।

## नषिकरष

तमाम समस्याओं के बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं कयिा जा सकता क मडि-डे मील कार्यक्रम ने आर्थकि और सामाजकि रूप से कमज़ोर बच्चों के वकिस में महत्त्वपूरण भूमकि अदा की है । हालाँकि इस कार्यक्रम में अभी भी सुधार की आवश्यकता है । आवश्यक है क सरकार योचना के कार्यान्वयन को लेकर अपने दृष्टकिण में परविरत्न करे और मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान दयिा जाए ।

**परशन:** मडि-डे मील कार्यक्रम के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए इसके समकष मौजूद चुनौतयिों पर चर्चा कीजयिे ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/meals-that-can-educate-the-young>

